

प्रेस विज्ञप्ति

क.भ.नि.सं. ने चालू वित्तीय वर्ष में 90 लाख से अधिक दावों का निपटान किया ।

क.भ.नि.सं. ने यू.ए.एन. आधारित सरल दावा फॉर्म जारी किए ।

क.भ.नि.सं. द्वारा 2 लाख से अधिक शिकायतों का निपटान किया गया ।

नई दिल्ली, 07.01.2016: क.भ.नि.सं. के दिसंबर माह में किए गए निष्पादन के विषय में बोलते हुए श्री के.के. जालान, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने कहा कि क.भ.नि.सं. ने अप्रैल से दिसंबर, 2015 के बीच 90.6 लाख दावों का निपटान किया । इनमें से 40% का निपटान 3 दिन के भीतर तथा लगभग 80% का निपटान 10 दिन के भीतर किया गया । 96% से अधिक दावों का निपटान निर्धारित 20 दिन की अवधि के भीतर किया गया ।

केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि.सं. की वित्त निवेश एवं लेखा परीक्षा समिति (एफ.आई.ए.सी.) ने एक महत्वपूर्ण नीति निर्णय लेते हुए इक्विटी एवं संबंधित निवेशों के लिए एकाउंटिंग पॉलिसी तथा पद्धति का अनुमोदन कर दिया । यह निर्णय प्रक्रिया में स्पष्टता लाने तथा ऐसी छूट प्राप्त स्थापनाओं के मार्गदर्शन हेतु लिया गया जिन्हें अब सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने संग्रह के 5% को इक्विटी बाजार में निवेश करना आवश्यक है ।

माह के दौरान यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यू.ए.एन.) के प्रसार एवं एक्टिवेशन पर पुनः जोर दिया गया तथा नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के लाभ के लिए देशभर के औद्योगिक समूहों में विशेष कैंप लगाने का निर्णय लिया गया । साथ ही, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नामांकन के पात्र नए कर्मचारियों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों के साथ सूचना के आदान-प्रदान हेतु तंत्र की भी शुरुआत भी की गई । इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को यू.ए.एन. के अग्रणी आबंटन के लिए एक सुविधा की शुरुआत की गई जिसके अंतर्गत नियोक्ता स्वयं अपने कर्मचारियों के लिए यू.ए.एन. का सृजन कर सकते हैं । साथ ही, यू.ए.एन. आधारित सरल दावा फॉर्मों की भी शुरुआत की गई जिसके द्वारा सदस्य नियोक्ता के सत्यापन अथवा हस्तक्षेप के बिना न्यूनतम आवश्यक विवरण देकर अपना भविष्य निधि दावा फार्म भर सकता है । यह सुविधा उन सदस्यों का उपलब्ध है जिनका यू.ए.एन. एक्टिवेट हो चुका है तथा आधार एवं बैंक खाते सहित के.वाई.सी. विवरण की उनके नियोक्ता द्वारा डिजिटल रूप में पुष्टि की जा चुकी है ।

क.भ.नि.सं. द्वारा 2014 में स्थापनाओं के ऑनलाईन पंजीकरण की शुरुआत की गई थी जिसके बाद संगठन द्वारा की जाने वाली कागजी कार्रवाई समाप्त हो गई तथा देशभर में कार्य करना आसान हो गया। एक और कदम आगे बढ़ाते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि ऑनलाईन आवेदन का अनुरोध करते समय नियोक्ता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर आधारित पुष्टि की जाए। इससे प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जांच के लिए स्थापना में जाने की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी तथा परिणामस्वरूप स्थापना के लिए कार्य करने के परेशानी मुक्त वातावरण का सृजन होगा। श्री के.के. जालान ने कहा कि शिकायत निपटान हमेशा से प्रमुख मुद्दा रहा है तथा माह के दौरान 20,000 से अधिक शिकायतों का निपटान किया गया एवं केवल 2,461 शिकायतें लंबित रहीं। यह उल्लेखनीय है कि 80% से अधिक शिकायतें 7 दिन से भी कम समय से लंबित थीं। कैलेंडर वर्ष 2015 में, क.भ.नि.सं. कुल 2,03,288 शिकायतों का निपटान करने में सफल रहा।

क.भ.नि.सं. ने अपने ग्राहकों के और अधिक करीब जाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए, सोशल मीडिया में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। 25 दिसंबर, 2015 को सुशासन दिवस के अवसर पर माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बंडारू दत्तात्रेय ने क.भ.नि.सं. के आधिकारिक फेसबुक एवं ट्विटर पेज की शुरुआत की। यह पेज www.facebook.com/socialepfo तथा www.twitter.com/socialepfo पर उपलब्ध है।

PRESS RELEASE

EPFO's Claim Settlement crosses 90 lakhs in the current fiscal

EPFO introduces UAN based simplified claim forms

More than 2 lakh grievances resolved by EPFO

New Delhi, 7.1.2016: While taking stock of the performance of EPFO in the month of December, Sh.K.K.Jalan, Central PF Commissioner noted that for the period April to December 2015, EPFO settled 90.6 lakh claims. Out of this 40% was settled within 3 days and close to 80% within 10 days. More than 96% of the claims were settled within the stipulated 20 day period.

In a major policy decision the Finance Investment and Audit Committee (FIAC) of the CBT, EPFO approved the accounting policy and method of accounting for equity and related investments. This decision is taken with a view to bring procedural clarity and also to serve as a guide to the various exempted establishments who also have to now invest 5% of their corpus in the equity market as per government guidelines

Dissemination and activation of Universal Account Number (UAN) was given renewed emphasis during the month and it has been decided to hold special camps in industrial clusters across the country for the benefit of employers and employees. Also a running mechanism of information exchange with jurisdictional Labour Commissioners is also envisaged for procuring information relating to new employees eligible to be enrolled under the schemes run by EPFO. Also a facility has been launched for upfront allotment of UAN to employees under which an employer can generate UAN for their employees themselves. Further, UAN based simplified forms have been introduced using which a member can file his PF claim by giving the bare minimum required details without the employer's attestation or intervention. This facility is available to those members whose UAN is activated and their KYC details including AADHAR and BANK ACCOUNT have been digitally authenticated beforehand by the employer.

EPFO had earlier in 2014 introduced online registration of establishments with the Organisation doing away with a lot of paperwork and contributing to greater ease of doing business in the country. Going a step further, it has been decided to introduce digital signature based authentication by the employer at the time of submission of online application requests. This would totally eliminate the requirement of Enforcement Officers' visit to the establishment for verification and thus would result in hassle free business environment for the establishment to function. Sh. K.K. Jalan stated that grievance redressal has always occupied the centrestage as more than 20,000 thousand grievances were redressed during the month and only 2,461 grievances were pending. It is noteworthy

that more than 80% of these grievances were pending for less than 7 days. In the calendar year 2015, EPFO was able to redress a total of 2,03,288 grievances.

Taking a step to bring EPFO closer to its clients, EPFO has made its presence felt on Social Media, the official Facebook and Twitter pages of EPFO were launched in the month of December 2015 by Hon'ble Union Minister of State, (Independent Charge), Labour & Employment, Sh. Bandaru Dattatreya on the occasion of Good Governance day on 25 December 2015. The pages are accessible at www.facebook.com/sociallepfo and www.twitter.com/sociallepfo